यह इस बात पर निर्भर करता है कि एक या दूसरा पक्ष अपील करता है या नहीं करता है, एक बार मामला किसी एक पक्ष द्वारा अपील में उसके समक्ष आ गया है। इसलिए इस तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता, यह पहले ही बताया जा चुका है कि जहां तक रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री का सवाल है, अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पहुंचा गया निष्कर्ष उसके द्वारा पर्याप्त रूप से समर्थित है और उल्लिखित गवाहों के साक्ष्य इसका समर्थन करते हैं। इसलिए यह पुनरीक्षण आवेदन खारिज किया जाता है, लेकिन मामले की परिस्थितियों में लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं है।

एन.के.एस

पुनरीक्षण सिविल

न्यायमूर्ति आर.एस नरूला के समक्ष

अमर सिंह,-याचिकाकर्ता।

बनाम

जगदीश और अन्य,-प्रतिवादी।

Civil Revision No. 245 of 1969

23 सितम्बर 1969

सिविल प्रक्रिया संहिता(1909 का V) - आदेश 1 नियम 3 - का दायरा और उद्देश्य - प्री-एम्प्शन के लिए मुकदमा - बिक्री से पहले पट्टे पर दी गई संपत्ति का मुकदमा - लीज डीड की वैधता - क्या ऐसे प्री-एम्प्शन सूट में चुनौती दी जा सकती है - संपत्ति का पट्टेदार - चाहे एक उचित पार्टी.

अभिनिर्धारित किया गया कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 1 के नियम 3 का उद्देश्य मुकदमों की बहुलता और पार्टियों को अनावश्यक खर्च से बचाना है, यदि इसे संबंधित वादियों और न्यायालय को शर्मिंदगी के बिना टाला जा सकता है। प्रतिवादी के रूप में एक से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने को उचित ठहराने के लिए, यह दिखाना आवश्यक नहीं है कि सभी प्रतिवादी मुकदमे में शामिल सभी राहतों और लेनदेन में रुचि रखते हैं। यदि प्री-एम्प्टर यह साबित करने में सक्षम है कि संपत्ति की बिक्री और पट्टा हालांकि दो अलग-अलग तारीखों पर निष्पादित किया गया है, तो वास्तव में एक ही लेनदेन का हिस्सा बनता है, और यह आगे पाया जाता है कि प्रति-एम्प्टर एक के रूप में प्रतिस्थापित होने का हकदार है प्रतिशोधी, यदि वह यह साबित कर सके कि यह या तो अमान्य है या वास्तव में इसका अस्तित्व ही नहीं है और यह एक दिखावा मात्र है, तो यह पट्टे से बचने के लिए प्रीम्प्टर के लिए खुला है। प्री-एम्प्शनर को निर्देश देना कि जब पट्टेदार को प्री-एम्प्शन के मुकदमे में एक पक्ष बनाया जाए तो उसका नाम काट दिया जाए और मुकदमे में पट्टेदार की सफलता की स्थिति में पट्टेदार को उसके खिलाफ दूसरे दौर की मुकदमेबाजी के लिए प्रेरित किया जाए। पूर्व-त्याग के लिए, उसी चीज़ को प्रोत्साहित करना होगा जिसे संहिता के आदेश 1 के नियम 3 द्वारा हतोत्साहित करने की मांग की गई है। यह उचित है कि यदि वादी मुकदमे की वास्तविकता या वैधता के बारे में निष्कर्ष चाहता है तो उसे मुकदमे में एक पक्ष बने रहना चाहिए।¬

आक्षेपित पट्टा-विलेख, क्योंकि अदालत के समक्ष कथित पट्टेदार को उपस्थित किए बिना उस मामले के संबंध में किसी भी निष्कर्ष को दर्ज करना ट्रायल कोर्ट के लिए प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होगा, (पैरा 5)

श्री राज कुमार गुप्ता, उप-न्यायाधीश, प्रथम वर्ग ,करनाल के न्यायालय के दिनांक 1 फरवरी, 1969 के आदेश के पुनरीक्षण के लिए याचिका सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 115 में कहा गया है कि वादी प्री-एम्प्टर को अलग नहीं किया जाना चाहिए। मुकदमा और इस मुकदमे में आक्षेपित पट्टे को पूर्व-मुक्ति के लिए चुनौती देने की अनुमति दी जाएगी।

याचिकाकर्ता की ओर से वकील एन.सी जैन।

मुनीश्वर पुरी औरप्रतिवादियों की ओर से अधिवक्ता आर.एन नरूला।

निर्णय

न्यायमूर्ति नरूला- ट्रायल कोर्ट के आदेश के संशोधन के लिए इस याचिका को दायर करने के लिए संक्षिप्त तथ्यों का पहले सर्वेक्षण किया जा सकता है, ताकि कानून के एकान्त क्षेत्राधिकार संबंधी प्रश्न की सराहना की जा सके, जिस पर इस मामले की सुनवाई में तर्क दिए गए हैं। संदर्भ की सुविधा के लिए, मैं इस मुकदमे के पक्षकारों को उनके शीर्षकों के अनुसार अधीनस्थ न्यायाधीश के न्यायालय में बुलाऊंगा।

(2) एम.एस.टी. निहाली प्रतिवादी संख्या 1, ने विवादित भूमि मान सिंह और उसके तीन भाइयों प्रतिवादी संख्या 2 से 5 को एक पंजीकृत विक्रय-पत्र, दिनांक 8 जून, 1967 द्वारा रुपये 18,000 में बेच दी। बिक्री से दो दिन पहले, यानी 6 जून, 1967 को, निहाली ने उस भूमि के संबंध में, जो इस मुकदमे की विषय-वस्तु है, अमर सिंह प्रतिवादी संख्या 6 के पक्ष में एक पंजीकृत पट्टा-विलेख निष्पादित किया, जो कि रहा है। वादी-प्रतिवादियों के वकील द्वारा प्रतिवादियों का ससुर होना बताया गया। साधु के बेटे जगदीश ने विक्रेता और विक्रेताओं के खिलाफ अपने पूर्व-खाली अधिकार के कथित अभ्यास में कब्जे के लिए मुकदमा दायर किया, और इसमें कथित पट्टेदार अमर सिंह प्रतिवादी नंबर 6 को भी शामिल किया। इसके बाद, लक्ष्मी चंद (दूसरे मुकदमे में वादी) ने भी अपने पूर्व-खाली अधिकार का प्रयोग करते हुए उसी भूमि पर कब्जे के लिए मुकदमा दायर किया। लक्ष्मी चंद ने याचिकाकर्ता अमर सिंह को भी अपने मुकदमे में प्रतिवादी बनाया।

(3)जगदीश द्वारा दायर मुकदमे के परिच्छेद 4 में, यह निम्नानुसार कहा गया था: -

> "वादी को नुकसान पहुंचाने और प्रतिवादी नंबर 1 के अपने श्रेष्ठ अधिकार से वंचित करने की दृष्टि से, प्रतिवादी नंबर 2 से 5 प्रतिवादियों और उनके पिता श्री कर्ता राम की मिलीभगत और सहमति से, एक उपकरण पर हमला किया गया और के पक्ष में एक फर्जी और मनगढ़ंत पट्टा-विलेख निष्पादित किया¬¬
>
> प्रतिवादी संख्या 6, ख़रीफ़ 1967 से रबी 1987 की अवधि के लिए, रुपये 300 प्रति वर्ष के मामूली किराए पर। और यह पट्टा-विलेख 6 जून, 1967 को निष्पादित और पंजीकृत किया गया था, अर्थात, बिक्री-विलेख के निष्पादन और पंजीकरण से केवल दो दिन पहले।"

वादपत्र के अनुच्छेद 7 में आगे यह अनुरोध किया गया था: -

> "प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी संख्या 6 के J के पक्ष में निष्पादित पट्टा-विलेख निम्नलिखित आधारों पर वादी पर बाध्यकारी नहीं है-
>
> (i) वास्तव में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी संख्या 6 के पक्ष में कोई पट्टा नहीं दिया गया था। दस्तावेज़ एक जालसाजी और मनगढ़ंत है और प्रतिवादी संख्या 2 से 5 द्वारा प्रतिवादी संख्या 6 के पिता के पक्ष में निष्पादित किया गया है। प्रेम सिंह प्रतिशोध का कानून, पूर्व-मुक्ति के अधिकार को पराजित करने के एकमात्र उद्देश्य के साथ;¬¬

(ii) कि कब्ज़ा पट्टेदार को नहीं दिया गया है और सब केवल एक मनगढ़ंत मामला है;

(iii) कि पट्टा और बिक्री एक ही लेन-देन का हिस्सा है, और इसलिए वादी इससे बंधा नहीं है।"

प्रतिवादियों (प्रतिवादी 2 से 5) के लिखित बयान के पैराग्राफ 4 में, वादी के पैराग्राफ 4 में लगाए गए आरोप से इनकार किया गया था, और यह जोड़ा गया था कि प्रतिवादी नंबर 1 ने निष्पादन से पहले वैध रूप से एक पट्टा-विलेख निष्पादित किया था। सेल-डीड, और लीज-डीड 1987 में समाप्त हो जाएगी। वादपत्र के पैराग्राफ 7 में दिए गए कथनों को अस्वीकार कर दिया गया था, और यह आरोप लगाया गया था कि लीज-डीड वैध थी, और विक्रेता द्वारा इससे पहले विधिवत निष्पादित किया गया था। बिक्री, क्योंकि वह अपने स्वयं के मामलों का प्रबंधन करने में असमर्थ थी। यह जोड़ा गया कि वर्तमान मुकदमे में वादी को पट्टे को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं था। आगे यह कहा गया कि विवादग्रस्त भूमि का कब्ज़ा पट्टेदार के पास था, और पट्टा और बिक्री अलग-अलग लेनदेन थे। अमर सिंह प्रतिवादी संख्या 6 के लिखित बयान में उठाई गई प्रारंभिक आपत्ति में यह आग्रह किया गया था कि उनके पक्ष में लीज-डीड के संबंध में मुकदमा अपने वर्तमान स्वरूप में चलने योग्य नहीं है।
विशिष्ट आपत्ति थी:-

"वादी जो प्रतिवादी नंबर T के स्थान पर कदम रखना चाहता है, उसे पहले लीज-डीड को अलग करवाना चाहिए और फिर प्री-एम्प्शन के लिए मुकदमा दायर करना चाहिए।"

(4) 1 फरवरी, 1969 को अपने आदेश से, अधीनस्थ न्यायाधीश, प्रथम श्रेणी, करनाल ने अमर सिंह द्वारा उठाई गई प्रारंभिक आपत्ति को खारिज कर दिया और मारुतिराव गोविंदराव बनाम नथमल जोदराज और अन्य (1) में *न्यायमूर्ति* पुराणिक, के फैसले पर भरोसा किया। यह माना गया कि वादी-प्री-एम्प्टर को एक अलग मुकदमे में नहीं धकेला जाना चाहिए, और उसे इस मुकदमे में प्री-एम्प्शन के लिए विवादित पट्टे को चुनौती देने की अनुमति दी जानी चाहिए। यह ट्रायल कोर्ट के उपरोक्त आदेश के खिलाफ है कि वर्तमान पुनरीक्षण याचिका प्रतिवादी संख्या 6 अमर सिंह द्वारा दायर की गई है।

श्री एन.सी. जैन ने जोरदार तर्क दिया:-

(i) कि वादी के पास प्री-एम्प्शन सूट में सफल हुए बिना और विक्रेता के जूते में कदम उठाए बिना लीज-डीड की वास्तविकता और वैधता को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है; (प्रारंभिक आपत्ति की तुलना में यह उलटा प्रस्ताव है)।

(ii) प्रतिवादी संख्या 6 के खिलाफ कोई राहत का दावा नहीं किया गया है, उसके पक्ष में निष्पादित पट्टे के विवाद को 'प्री-एम्प्शन सूट' में लाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, और इसे बाद के मुकदमे में लड़ने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए, यदि वादी छूट के अपने अधिकार को साबित करने में सफल हो जाता है और भूमि पर कब्जे के लिए डिक्री प्राप्त करने में सक्षम हो जाता है;¬

(iii) मारुतिराव गोविंदराव के मामले (1) में नागपुर उच्च न्यायालय का निर्णय, बरार भूमि राजस्व संहिता की धारा 183 की विशिष्ट विशेषताओं पर आधारित है, क्योंकि पंजाब प्री-एम्प्शन एक्ट में कोई संबंधित प्रावधान नहीं है; और

(iv) यदि नागपुर मामले और वर्तमान मामले के बीच कोई अंतर नहीं पाया जा सकता है, तो नागपुर मामले में*न्यायमूर्ति* पुराणिक, का निर्णय सही कानून नहीं बताता है।

(5) सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 1 के नियम 3 में कहा गया है: -

"सभी व्यक्तियों को प्रतिवादी के रूप में शामिल किया जा सकता है जिनके खिलाफ एक ही कार्य या लेन-देन या कृत्यों या लेन-देन की श्रृंखला के संबंध में या उससे उत्पन्न होने वाले राहत का कोई अधिकार मौजूद होने का आरोप है, चाहे संयुक्त रूप से, अलग-अलग या

विकल्प में, जहां यदि ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ अलग-अलग मुकदमे लाए जाते, तो कानून या तथ्य का कोई सामान्य प्रश्न उठता।

नियम 3 को लागू करने के लिए पूर्ववर्ती शर्तों में से एक यह है कि राहत का अधिकार एक ही कार्य या लेनदेन, या कृत्यों या लेनदेन की श्रृंखला के संबंध में या उससे उत्पन्न होना चाहिए। जबकि वादी ने विशेष रूप से आग्रह किया है कि पट्टा और बिक्री एक ही लेनदेन का हिस्सा हैं, प्रतिवादियों ने इस आरोप का खंडन किया है। ट्रायल कोर्ट द्वारा पक्षों के बीच मुद्दे के उस हिस्से पर अभी तक कोई निर्णय नहीं दिया गया है। आदेश 1 के नियम 3 का उद्देश्य मुकदमों की बहुलता और पक्षों को अनावश्यक खर्च से बचाना है, यदि इसे संबंधित वादियों और न्यायालय को शर्मिंदगी के बिना टाला जा सकता है। यह स्थापित कानून है कि प्रतिवादी के रूप में एक से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने को उचित ठहराने के लिए, यह दिखाना आवश्यक नहीं है कि सभी प्रतिवादी मुकदमे में शामिल सभी राहतों और लेनदेन में रुचि रखते हैं। न ही मुझे इस बात की जानकारी है कि कभी भी यह निर्धारित किया गया है कि किसी को भी प्रतिवादी के रूप में तब तक शामिल नहीं किया जा सकता जब तक कि उसके खिलाफ कुछ विशिष्ट राहत का दावा न किया गया हो। प्रोफार्मा पार्टियों का प्रतिवादी के रूप में शामिल होना सर्वविदित है। यदि वादी यह साबित करने में सक्षम है कि बिक्री और पट्टा, हालांकि दो अलग-अलग तिथियों पर निष्पादित किया गया है, वास्तव में

(1) एआईआर 1947 नागपुर 229

एक ही लेनदेन का हिस्सा है, और यह आगे पाया जाता है कि वादी प्रतिवादी के स्थान पर प्रतिवादी के रूप में प्रतिस्थापित होने का हकदार है। 2 से 5 तक, संभवतः वादी के लिए पट्टे से बचना संभव होगा यदि वह यह साबित कर सके कि यह या तो अमान्य है या वास्तव में अस्तित्वहीन है और एक मात्र दिखावा है। इस बात पर विवाद नहीं किया गया है कि भले ही याचिकाकर्ता को प्रतिवादियों की सूची से बाहर कर दिया गया हो, उसके खिलाफ कब्जे के लिए एक मुकदमा इस आधार पर कायम रखा जा सकता है कि विवाद में भूमि का कोई वैध पट्टा वास्तव में प्रतिवादी द्वारा उसके पक्ष में कभी नहीं बनाया गया है। नंबर 1, वादी प्री-एम्पशन मुकदमे में सफल होने के बाद, और शेष प्री-एम्पशन धन जमा करके संपत्ति का मालिक बन जाता है। वादी को वर्तमान मुकदमे से प्रतिवादी संख्या 6 का नाम हटाने का निर्देश देना, और पूर्व-मुक्ति के मुकदमे में वादी की सफलता के मामले में वादी को वर्तमान याचिकाकर्ता के खिलाफ मुकदमे के दूसरे दौर में ले जाना, उसी चीज़ को प्रोत्साहित करना जिसे सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 1 के नियम 3 द्वारा हतोत्साहित किया जाना है। यदि वादी ने प्रतिवादी संख्या 6 को पक्षकार नहीं बनाया था और यदि प्रतिवादी संख्या 6 प्री-एम्प्शन के मुकदमे में एक पक्ष बनने के लिए आगे आया था, तो प्रतिवादी का आवेदन आम तौर पर सफल नहीं होता क्योंकि वह निश्चित रूप से एक आवश्यक पक्ष नहीं है 'पूर्व-मुक्ति के लिए मुकदमा करने के लिए। संहिता के आदेश 1 के नियम 3 में किया गया प्रावधान केवल सक्षम बनाता है और वादी पर उन प्रतिवादियों को फंसाने का दायित्व नहीं डालता है जिनके खिलाफ विभिन्न¬¬¬¬ राहत का दावा किया जा सकता है, भले ही प्रतिवादी संख्या 6 के खिलाफ कोई विशिष्ट राहत का दावा नहीं किया गया हो। वैसे यह उचित है, लेकिन उचित है कि यदि वादी विवादित पट्टे की वास्तविकता या वैधता के बारे में निष्कर्ष चाहता है तो उसे मुकदमे में एक पक्ष बने रहना चाहिए। -विलेख, क्योंकि अदालत के समक्ष कथित पट्टेदार को उपस्थित किए बिना उस मामले के संबंध में किसी भी निष्कर्ष को दर्ज करना ट्रायल कोर्ट के लिए प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होगा।

(6) मारुतिराव गोविंदराव के मामले (1) (सुप्रा) में, वादी-प्री-एम्प्टर ने विक्रेता और विक्रेताओं के साथ सह-प्रतिवादी के रूप में भूमि के पट्टेदार को मुकदमे में शामिल किया था। वादी का आरोप यह था कि पट्टा-विलेख फर्जी था और वादी के पूर्व-मुक्ति के अधिकार को बाधित करने की दृष्टि से मूल विक्रेता से मिलीभगत करके प्राप्त किया गया था। पट्टेदार सहित प्रतिवादियों ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष तर्क दिया कि पट्टेदार मुकदमे में एक आवश्यक पक्ष नहीं था। ट्रायल कोर्ट ने माना कि लीज-डीड की वास्तविकता या अन्यथा पर प्री-एम्प्शन मुकदमे में विचार नहीं किया जा सकता है। ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ पुनरीक्षण याचिका को *न्यायमूर्ति* पुराणिक, ने इस आधार पर अनुमति दी थी कि बरार भूमि राजस्व संहिता की धारा 183 की उप-धारा (2) अदालत को लेनदेन की जांच करने और निष्पक्ष विचार तय करने की अनुमति देती है। ब्याज को पूर्व-खाली करने की मांग की गई। यह माना गया था कि चूंकि वादी अदालत से बिक्री के लेन-देन की जांच करने के लिए कह रहा था, और लीज-डीड के संबंध में बिक्री-पत्र में कुछ विवरण थे, इसलिए उन दावों की सत्यता की जांच करना न्यायालय के लिए खुला था। वर्तमान मामले में श्री जैन का कहना है कि विक्रय-पत्र में पट्टा-विलेख का कोई उल्लेख नहीं है। उत्तरदाताओं के विद्वान वकील उस आरोप को स्वीकार या अस्वीकार करने की स्थिति में नहीं थे। न तो विक्रय-पत्र और न ही उसकी कोई प्रति मुझे दिखाई गई है। भले ही यह मान लिया जाए कि बिक्री-विलेख में लीज-डीड के बारे में कोई विवरण नहीं है, फिर भी वादी के लिए यह आरोप लगाना और साबित करना खुला है कि बिक्री-डीड और लीज-डीड, हालांकि अलग-अलग तारीखों पर निष्पादित किए गए हैं। अलग-अलग कागजात, वास्तव में एक लेनदेन बनाते हैं। इस मामले में वास्तविक कीमत काफी कम होने की दलील भी दी गयी है. मारुतिराव गोविंदराव के मामले (1) में *न्यायमूर्ति* पुराणिक ने कहा कि विद्वान न्यायाधीश को ऐसे किसी कानून की जानकारी नहीं थी जो अदालत को मुकदमे की सुनवाई करने से रोकता है, और वादी वास्तविक कब्जे के बारे में सवाल पूछने का हकदार था। वादी को दूसरा मुकदमा दायर करने के लिए प्रेरित करने के बजाय संपत्ति को पूर्व-खाली मुकदमे में ही मंजूरी दे दी गई। यह माना गया कि कथित पट्टेदार इन परिस्थितियों में मुकदमे में आवश्यक पक्ष था क्योंकि पट्टे की वैधता के बारे में वादी द्वारा की जाने वाली जांच कथित पट्टेदार की अनुपस्थिति में नहीं की जा सकती थी। न ही मैं इनमें कोई भौतिक अंतर देख पा रहा हूं बरार मामला और प्रासंगिक कानूनी प्रावधान के सवाल पर वर्तमान मामला। बरार भू-राजस्व संहिता की धारा 183 मुझे नहीं दिखाई गई है। लेकिन हाई कोर्ट के फैसले में उस प्रावधान के बारे में जो कुछ भी कहा गया है, उससे ऐसा लगता है कि पंजाब प्री-एम्प्शन एक्ट की धारा 25 का प्रावधान, जो कोर्ट को यह निर्धारित

करने के लिए अधिकृत करता है कि जिस कीमत पर बिक्री बताई गई है। अच्छे विश्वास में तय किया गया है या नहीं, और नकारात्मक निष्कर्ष के मामले में बाजार-मूल्य जे को मुकदमे के प्रयोजनों के लिए कीमत के रूप में तय करना, बराड़ भूमि राजस्व संहिता की धारा 183 के बराबर है। श्री जैन मुझे ऐसा कोई कानून नहीं दिखा पाए हैं जो पट्टेदार को विक्रेता और विक्रेता के साथ सह-प्रतिवादी के रूप में शामिल होने से रोकता हो, जहां मुकदमे में संपत्ति किसी तीसरे व्यक्ति के कब्जे में होने का आरोप है। जो पट्टेदार के रूप में दावा करता है, और जिसके पट्टे की वास्तविकता पर वादी द्वारा विवाद किया गया है। मुझे लगता है कि प्री-एम्प्शन के मुकदमे में सफल होने के बाद उसे कब्जे के लिए एक अलग मुकदमे में ले जाना वादी के साथ अन्याय होगा। हालाँकि, यदि वादी प्री-एम्पशन मुकदमे में विफल रहता है, तो कथित पट्टेदार को इस मुकदमे की रक्षा में उसके द्वारा किए गए खर्चों की सीमा को छोड़कर किसी भी तरह से नुकसान नहीं होगा, जिसके लिए उसे मुआवजा देने के लिए संहिता में पर्याप्त प्रावधान हैं।

(7) श्रीमान जैन ने दोलत राम सिंघी बनाम एस. अमरचंद सारदा और अन्य (2) मामले में प्रथम न्यायिक आयुक्त, अजमेर के फैसले पर भरोसा किया। उस मामले में आत्मा चरण, जे.सी. ने माना कि प्री-एम्शन के मुकदमे में मुकदमे में जमीन का गिरवीदार एक आवश्यक पक्ष नहीं है। यह देखा गया कि गिरवीदार को गवाह के रूप में पेश किया जा सकता है। विद्वान न्यायिक आयुक्त द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष के अनुसार, डोलट राम सिंह बनाम मामले (2) में गिरवीदार और पूर्व-खालीकर्ता के बीच कोई विचारणीय मुद्दा नहीं था। यह दोनों पक्षों का स्वीकृत मामला था कि मोचन की इक्विटी का बाजार मूल्य 2,000 रुपये था। गिरवीदार के विरुद्ध वादपत्र में कोई राहत नहीं मांगी गई थी। एकमात्र विवाद गिरवीदार को पक्षकार बनाने के कारण वादपत्र पर देय अदालती फीस से संबंधित था, और वह भी एक आकस्मिक मामला था। यह उन परिस्थितियों में था कि विद्वान न्यायिक आयुक्त ने माना कि गिरवीदार मुकदमे में एक आवश्यक पक्ष नहीं था। अजमेर मामले के तथ्य मेरे सामने मौजूद मामले से स्पष्ट रूप से भिन्न हैं। वास्तव में नागपुर उच्च न्यायालय के *न्यायमूर्ति* पुराणिक का फैसला चारों खाने चित होता नजर आ रहा है। मेरे द्वारा पहले ही दर्ज किए गए कारणों के लिए। मैं *न्यायमूर्ति* पुराणिक द्वारा व्यक्त विचार से सम्मानपूर्वक सहमत हूं। क्षेत्र मोहन में त्रिपुरा के न्यायिक आयुक्त का निर्णय

नाथ सरमा बनाम मोहम्मद सादिर बेपारी और अन्य (3), एक विपरीत मामले से संबंधित है। एक व्यक्ति विशिष्ट प्रदर्शन के लिए एक मुकदमे में प्रतिवादी के रूप में शामिल होना चाहता था, जो कि उस संपत्ति के पूर्व स्वामित्व के आधार पर कहा गया था जो विशिष्ट प्रदर्शन के लिए समझौते में प्रवेश करने से पहले अस्तित्व में थी। यह देखा गया कि ऐसा व्यक्ति विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 27(बी) या (सी) के तहत नहीं आता था, और वादी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कोई विशिष्ट राहत प्राप्त नहीं कर सका। ऐसा होने पर, यह माना गया कि ऐसा कोई व्यक्ति वादी पर उसे एक पक्ष बनाने पर जोर नहीं दे सकता है, जिससे विशिष्ट प्रदर्शन के लिए मुकदमे को शीर्षक पर एक में परिवर्तित किया जा सके और मुकदमे में उन मामलों को पेश किया जा सके जो उसमें मांगी गई राहत प्राप्त करने के लिए बिल्कुल विदेशी हैं। मैंने पहले ही देखा है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 1 के नियम 3 में निहित प्रावधान वादी के लाभ के लिए है, और केवल वादी को किसी भी व्यक्ति को पक्षकार बनाने में सक्षम बनाता है, जिसे उस नियम द्वारा प्रतिवादी के रूप में पेश करने की अनुमति है। , लेकिन उक्त प्रावधान किसी भी व्यक्ति को मुकदमे में पक्षकार बनने पर जोर देने का अधिकार नहीं देता, भले ही वादी उसे पक्षकार बनाने की इच्छा न रखता हो।

(8) दो वादीगणों के लिए मेसर्स मुनीश्वर पुरी और आरएन नरूला अधिवक्ताओं ने रामभाऊ वामनराव जोशी और अन्य बनाम गणेश देवराव पाटिल और अन्य (4) में *न्यायमूर्ति* पाध्ये, के फैसले का हवाला दिया। उस मामले में कुछ प्रतिवादियों को शामिल करने की अनुमति दी गई थी क्योंकि यह पूरी तरह से आपत्तिजनक पाया गया था क्योंकि इससे प्रतिवादियों के लिए मुकदमा किसी भी तरह से परेशान करने वाला या परेशान करने वाला नहीं होता। उस मामले के तथ्य अलग-अलग हैं और *न्यायमूर्ति* पाध्ये, का निर्णय, उत्तरदाताओं के लिए कोई प्रत्यक्ष और वास्तविक सहायता नहीं है, हालांकि यह उनके मामले का समर्थन करता है।

(9) श्री पुरी ने अंततः तर्क दिया कि ट्रायल कोर्ट का आदेश सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 115 के अर्थ में "निर्णयित मामले" की श्रेणी में नहीं आता है, और इसलिए, उस आदेश के खिलाफ पुनरीक्षण के लिए यह याचिका सक्षम नहीं है। जिस दृष्टि से मैंने विवाद के गुण-दोषों को समझ लिया है, इस अकादमिक प्रश्न में जाना अनावश्यक है। जैसा कि वर्तमान में सलाह दी गई है, मैं यह सोचने के लिए इच्छुक हूं कि क्या यह

दिखाया जा सकता है कि ट्रायल कोर्ट के पास आगे बढ़ने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है वर्तमान मुकदमे में प्रतिवादी-याचिकाकर्ता के खिलाफ मुकदमे के साथ, इसके विपरीत ट्रायल कोर्ट का आदेश धारा 115 के अर्थ में "मामले का फैसला" माना जाएगा।

(10) मेरे द्वारा पहले ही दर्ज किए गए कारणों के आधार पर, मेरी राय है कि ट्रायल कोर्ट द्वारा अनुमति दिए जाने वाले आदेश में कोई अपवाद नहीं लिया जा सकता है प्रतिवादियों की सूची से प्रतिवादी संख्या 6 का नाम हटाए बिना मुकदमा आगे बढ़ाया जाए। इसलिए, यह पुनरीक्षण याचिका विफल हो जाती है और जुर्माने के साथ खारिज की जाती है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

ममता,
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
रोहतक, हरियाणा।